900एम" का प्रयोग किया। किसान बहुत खुश हुए जब पौधा तगड़ा हुआ। और भी ज्यादा खुश वे तब हुए जब पौधे में डेढ़-डेढ़ फीट के बाल आए किन्तु जैसे ही बाल छील कर दाना देखना चाहा तो उनके पैरो तले जमीन खिसक गयी क्योंकि सभी बालों मे दाने थे ही नहीं। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गूंज दिल्ली तक पहुंची। केन्द्रीय जांच कमेटी गयी किन्तु लाखों लोगों को अब भी न्याय मिलने का इंतजार है, हालांकि उनका दिल बैठा जा रहा है। जांच कमेटी ने जांच के नियमों की खुले आम अवहेलना की। किसानों के उग्र आक्रोश के कारण जांच कमेटी के साथ गये हुए बीज निदेशक को घोषणा करनी पड़ी कि पिछले साल के बीज में कुछ परिवर्तन किया गया था और इस बीज में दाने छोटे नुकीले आने चाहिए थे। शायद मिट्टी और मौसम की गड़बड़ी से दाने नहीं आए। मैं बिहारी किसानों के साथ मान्सेंटो कम्पनी द्वारा बरती गयी आपराधिक लापरवाही एवं बीज घोटाला कर करोड़ों का व्यापार कर गरीब किसानों की खून-पसीने की कमाई हड़पने का आरोप लगाती हूं और मांग करती हूं कि मान्सेंटो कम्पनी पर आपराधिक मुकदमा दायर कर इसे ब्लैकलिस्टिड किया जाए तथा निर्वंश बीज बेचकर मालामाल कम्पनी से पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करती हूं कि आर्थिक तंगी से गुजर रही बिहार सरकार के सामने हजारों हेक्टेयर फसल के इस प्रकार खराब हो जाने के कारण जो संकट आ गया है, उसमें केन्द्रीय राहत कोष से राहत राशि अविलम्ब उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश) : महोदया, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : महोदया, मैं माननीय सदस्या से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

Demand for construction of alternative emergency rail route in Kashmir

श्री कृपाल परमार (हिमाचल प्रदेश) : धन्यवाद उपसभापति महोदया, जैसा कि आपको विदित है कि कश्मीर देश का मुकुट है और यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यहां सेना को निर्बाध गति से आपूर्ति हेतु एक रेल एवं एक सड़क मार्ग है। जम्मू के इस क्षेत्र को सामरिक दृष्टि से चिकन नैक के नाम से जाना जाता है तथा रेल एवं सड़क मार्ग दोनों ही इसी चिकन नैक से होकर गुजरते हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान की मारक दूरी के अंदर स्थित है।

यदि भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान अपनी चाल में कामयाब हो जाए और इस मार्ग को अवरूद्ध कर दे तो हमारे पास सेनाओं की सप्लाई के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक सड़क का निर्माण भारत-पाक सीमा से हटकर ऊना, (रणजीत सागर) डैम होकर उधमपुर तक किया जा रहा है। मैं आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में प्रथम एवं एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन तलवाड़ा-ऊना-नंगल का निर्माण कार्य चल रहा है। इस रेलवे लाइन का सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा उक्त

सड़क मार्ग के साथ-साथ चलता है जिसका निर्माण किया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस रेल मार्ग को तलवाड़ा से आगे नूरपुर होते हुए ऊधमपुर तक प्राथमिकता के आधार पर पूरा बनाया जाए जिससे कि एक वैकल्पिक रेल मार्ग सेनाओं की सप्लाई बनाए रखने हेतु उपलब्ध हो सके।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से रक्षा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस रेल मार्ग का वैकल्पिक मार्ग के रूप में रेल मंत्रालय के साथ तलवाड़ा से आगे बढ़ाने हेतु संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कराएं और प्राथमिकता के आधार पर रेल के इस वैकल्पिक मार्ग का निर्माण कराएं। धन्यवाद।

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, मैं अपने आप को इससे सम्बद्ध करता हूं।

Postponement of recovery of loans from farmers in Gujarat due to drought

SHRI BACHANI LEKHRAJ (Gujarat): Madam, this year, in about 12 States of the country, there have been acute drought and scarcity conditions. The nationalised and cooperative banks have postponed the recovery of loans and interest in Rajasthan and other States. In Gujarat, in 18 out of 25 districts, there are acute drought conditions. Thousands of villages have been declared to be facing scarcity conditions by the Gujarat State Government, and various relief works have been undertaken, including the setting up of many cattle camps. The Central Government has also given financial assistance to the Gujarat State for carrying out the relief work. A special team of the Ministry of Agriculture had also visited the scarcity areas of Gujarat. Despite that, the Government has still not issued the orders for the postponement of the recovery of loans and interest by the said banks. The said banks are taking legal steps and adopting coercive measures, either directly or through the courts.

It is, therefore, necessary, in view of the pitiable condition of the loanee farmers, that the Government of India gives instructions to such banks for the postponement of the recovery of loans for, at least, one year.

SHRI JAYANTILAL BAROT (Gujarat): Madam, I associate myself with what the hon. Member has mentioned.